Times of India- 16- February-2024

'BRS Turned Blind Eye To RLIS' ■ Min Claims Level-Playing Field For Investors ■ 'Free Bus Raised Endowment Revenue'

CM Blames KCR For 'Injustice' In Krishna Water Share

Koride.Mahesh
@timesgroup.com

Hyderabad: The state assembly witnessed a war of words between ruling Congress and BRS over alleged handing over of irrigation projects to Krishna River Management Board (KRMB) and also Telangana's share in Krishna waters.

Speaking in the assembly on Friday, chief minister A Revanth Reddy blamed the previous BRS govt for doing injustice to Telangana on sharing of Krishna water. He said former CM K Chandrasekhar Rao accepted 299 tmcft of water for Telangana and 512 tmcft to Andhra Pradesh, which was incorporated in AP Reorganisation Act, 2014.

"BRS MP Nama Nageswara Rao raised a question in Lok Sabha over Krishna waters. The Centre replied that the previous BRS govt signed accepting 512 tmcft to AP and 299 tmcft to Telangana in various meetings since 2014," Revanth said while reading out the reply by the Centre on Krishna waters. He said BRS had completely surrendered Telangana's interests to KRMB and AP.

ASSEMBLY IN SESSION

The CM said the previous BRS govt did not bat an eyelid when AP govt began constructing Rayalaseema Lift Irrigation Scheme (RLIS) to draw 8 tmcft and Pothireddypadu Head Regulator. "While AP made plans to draw 12 tmcft of water every day, our projects in Telangana cannot draw even 2 tmcft," he said. Revanth alleged that an agreement on RLIS was reached during KCR-YS Jagan Mohan Reddy meeting in Hyderabad a few years ago.

BRS GAVE AWAY T TO KRMB & AP: CM

- CM Revanth says previous BRS govt did not bat an eyelid when AP govt began constructing Rayalaseema Lift Irrigation Scheme to draw 8 tmcft
- Despite AP cops entering Nagarjuna Sagar project, previous BRS govt didn't do anything initially, CM says
- Says BRS had surrendered Telangana's interests to KRMB and AP

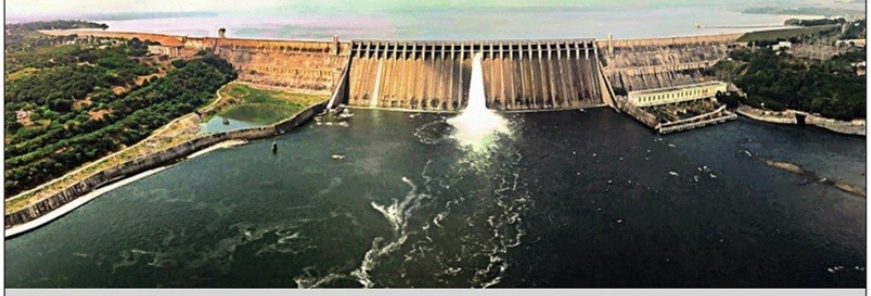

> BRS MP Nama Nageswara Rao raised a question in Lok Sabha over Krishna waters. The Centre replied that the previous BRS govt signed accepting 512 tmcft to AP and 299 tmcft to Telangana in various meetings since 2014 — **Revanth Reddy** | CHIEF MINISTER

The CM said despite AP cops entering Nagarjuna Sagar project inside Telangana's territory, the previous BRS govt didn't do anything and finally, CRPF protection is being given to the project.

He said opposition parties should join hands with the ruling party if there are issues pertaining to inter-state matters. He advised BRS leaders to stage a dharna in Delhi.

Both irrigation minister N Uttam Kumar Reddy and ex-minister T Harish Rao were involved in an argument over KRMB issue. Harish Rao said after just two meetings with Union Jal Shakti ministry and KRMB, the Congress govt had agreed to hand over Krishna projects to KRMB. He wondered why CRPF was stationed at Nagarjuna Sagar.

Uttam said the state govt would not hand over the projects to KRMB. He said in meetings with the Centre and KRMB, Telangana irrigation secretary had objected to the proposal and asked for status quo. Uttam requested speaker Gaddam Prasada Rao to allow a special discussion on irrigation.

Times of India- 16- February-2024

Mallanna Sagar in seismic zone, T ignored NGRI reports in 2020

Koride.Mahesh
@timesgroup.com

Hyderabad: In a significant observation, CAG said Mallanna Sagar reservoir was located in a seismic zone and there was a deep-seated vertical fault in the reservoir site. The National Geophysical Research Institute, which had submitted a preliminary report on Mallanna Sagar to the irrigation department in Dec 2020, said detailed studies need to be done as earthquakes in united Andhra Pradesh and Maharashtra's Latur caused damage to structures in Telangana region.

"In June 1983, Medchal area experienced an earthquake of 4.9 magnitude. This earthquake had a depth of more than 15 km and was felt significantly up to a distance of 200 km because of its deep-seated origin," CAG said.

Earthquake epicentre

It added that the epicentre distance of this earthquake is about 20 km from the Mallanna Sagar reservoir site. CAG said the irrigation department approached NGRI in Aug 2016 to get a site-specific seismic study before approval of the drawings for the reservoir. But the irrigation department awarded the work to the contractor in Dec 2017 and asked contractor to complete the work by Dec 2020.

"Keeping in view of the historical seismicity status of the region, an earthquake of magnitude 5 or more is likely to cause damage to non-engineered structures. Hence, any installation planned should be in conformity to withstand the levels of ground shaking," CAG said.

Despite the recommendations of NGRI, the state govt did not conduct any detailed survey of the location and went ahead with the construction of Mallanna Sagar, CAG added.

Dainik Jagran- 16- February-2024

पाकिस्तान नहीं जाएगा रावी का पानी

कठुआ : 45 साल का सपना और लंबा संघर्ष। अब पाकिस्तान बहकर जा रहा रावी का पानी अब जम्मू-कश्मीर और पंजाब की बंजर हो रही करीब 37 हजार हेक्टेयर जमीन हरियाली लाएगा। इसमें से 32 हजार हेक्टेयर भूमि जम्मू-कश्मीर में ही है। केंद्र सरकार के सहयोग से वर्ष 2018 में आरंभ हुई शाहपुर कंडी परियोजना का ज्यादातर काम पूरा कर लिया गया है। गुरदासपुर के शाहपुर कंडी में बांध बनकर तैयार है और इसी माह 25 फरवरी को बांध में जल भंडारण होने लगेगा। ● पेज 14

पाकिस्तान नहीं जाएगा रावी का पानी

जम्मू-कश्मीर में लाएगा हरियाली, शाहपुर कंडी परियोजना का कार्य पूरा

राकेश शर्मा ● कठुआ

45 साल का सपना और लंबा संघर्ष। पाकिस्तान बहकर जा रहा रावी का पानी अब जम्मू-कश्मीर और पंजाब की बंजर हो रही करीब 37 हजार हेक्टेयर जमीन हरियाली लाएगा। इसमें से 32 हजार हेक्टेयर भूमि जम्मू-कश्मीर में ही है। केंद्र सरकार के सहयोग से वर्ष 2018 में आरंभ हुई शाहपुर कंडी परियोजना का ज्यादातर काम पूरा कर लिया गया है।

गुरदासपुर के शाहपुर कंडी में बांध बनकर तैयार है और इसी माह 25 फरवरी को बांध में जल भंडारण होने लगेगा। उसके बाद रावी-तवी नहर के माध्यम से किसानों के खेतों तक यह पानी पहुंचाया जाएगा। इसके साथ इस परियोजना से 200 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य है। इस परियोजना के लिए करीब 2793 करोड़ रुपये की लागत आई है। बता दें कि सिंधु जल समझौते के अनुसार, रावी नदी के पूरे पानी पर भारत का हक है। फिर भी रावी से कुछ पानी बहकर पाकिस्तान जा रहा था।

शाहपुर कंडी बांध को रणजीत सागर से 11 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में बनाया गया है। अब इस पानी को बांध बनाकर रोका जाना है। बांध बनकर तैयार हो चुका है। भंडारण का कार्य आरंभ होने के बाद यहां एक कृत्रिम झील आकार ले लेगी और उसके बाद इससे जम्मू-कश्मीर और पंजाब की नहरों के माध्यम से खेतों तक पानी पहुंचाया जाएगा।

परियोजना से जम्मू-कश्मीर को उसके हक का 1150 क्यूसेक पानी मिलना शुरू हो जाएगा। इससे पानी के अभाव में कठुआ, हीरानगर और सांबा की बंजर हो चुकी जमीन सिंचित होगी और यहां के खेतों में भी हरियाली लहलहाएगी।

वर्ष 1979 में रणजीत सागर बांध के निर्माण के दौरान जम्मू-कश्मीर के किसानों को भी उनके हक का पानी दिलाने का वादा किया गया था, लेकिन यहां के किसानों की आवाज किसी ने नहीं सुनी। जम्मू-कश्मीर ने यह पानी लेने के लिए करीब 60 किलोमीटर लंबी रावी-तवी नहर का निर्माण भी वर्ष 1996 में कर लिया था। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में नई सरकार बनने के बाद केंद्रीय राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने इस मुद्दे को लगातार उठाया और केंद्र ने इस परियोजना के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई। अब पंजाब के शाहपुर कंडी क्षेत्र में रावी नदी पर बांध बनकर तैयार है।

● नहरों के माध्यम से जम्मू-कश्मीर की सूखी जमीन होगी सिंचित

● सिंधु जल समझौते के अनुसार रावी के पूरे पानी पर भारत का है हक

1,150 क्यूसेक पानी जम्मू-कश्मीर का मिलेगा

200 क्यूसेक पानी पंजाब को मिलेगा

200 मेगावाट बिजली उत्पादन का भी लक्ष्य

2,793 करोड़ रुपये आई परियोजना की लागत

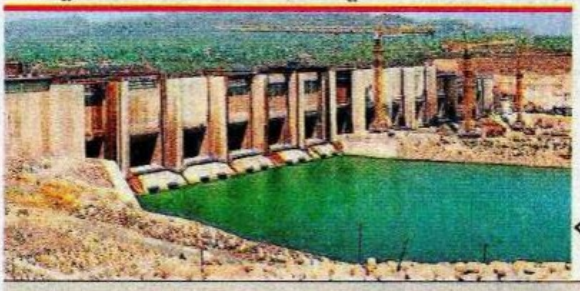

<< पंजाब के शाहपुर कंडी क्षेत्र में रावी नदी पर बांध बनकर तैयार है ● जागरण

45 वर्ष से जम्मू-कश्मीर की पूर्व सरकारों की भेदभावपूर्ण नीतियों के चलते शाहपुर कंडी जैसी महत्वपूर्ण परियोजना अधर में लटकी थी। वर्ष 2014 में केंद्र में जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो उन्होंने इस मुद्दे को उनके समक्ष उठाया। आज शाहपुर परियोजना बनकर तैयार है। मैं विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार जताता हूं।

- डा. जितेंद्र सिंह, प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्यमंत्री

Dainik Jagran- 16- February-2024

धान पर जोर ने बढ़ाया पंजाब का जल संकट

- हर साल में एक मीटर तक गिर रहा भूजल का स्तर, 20 साल से ज्यादा नहीं चलेगा पानी
- सिर्फ 1.2 प्रतिशत जमीन लघु सिंचाई के दायरे में, दूसरी फसलों का घट रहा रकबा

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : न्यूनतम समर्थन मूल्य की संवैधानिक गारंटी के लिए फिर से शुरू हुए विरोध प्रदर्शनों में सबसे आगे पंजाब में किसान धान में एमएसपी का लाभ उठाने में जितने आगे हैं, उतना ही कृषि के विविधीकरण में पीछे और पर्यावरण की चुनौतियों का सामना करने में एकदम ढुलमुल।

पंजाब में कृषि और खासकर धान की विविधता का दायरा सीमित है। इस फसल का रकबा तेजी से बढ़ता जा रहा है। 1980 में 28.12 लाख हेक्टेयर से 2023 में 31.93 लाख हेक्टेयर तक, लेकिन इस दौरान बाकी सभी फसलें (गन्ना, कपास, गेहूं और मक्का) उतनी ही तेजी से पीछे छूटती गईं। इसकी वजह उर्वरक सब्सिडी, सस्ती बिजली (1970-1990 तक फ्लैट रेट और फिर पूरी तरह मुफ्त), 1967 से एमएसपी आधारित गारंटीड खरीद और सिंचाई में बेहिसाब पानी के इस्तेमाल की सुविधा है। आज हालत यह है कि 1980 में मक्के की खेती का जो रकबा 3.82 लाख हेक्टेयर था, वह 2023 में घटकर एक लाख हेक्टेयर पर आ गया है। यही कपास के मामले में भी हुआ है। 43 साल में इसका रकबा 6.49 लाख हेक्टेयर से 1.80 लाख हेक्टेयर पर आ गया।

इसके गंभीर दुष्परिणाम अनुभव किए जाने लगे हैं। सबसे बड़ा दुष्प्रभाव यह है कि भूजल का स्तर हर साल एक मीटर नीचे जा रहा है। सरकार के एक अधिकारी के अनुसार पंजाब के 78 प्रतिशत ब्लाक अतिदोहन वाले हैं और अगर एक सरकारी अध्ययन की रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए तो पंजाब के पास केवल 20 साल का पानी बचा है। रिपोर्ट के अनुसार समस्या इसलिए गंभीर होती जा रही है, क्योंकि कृषि के आधुनिकीकरण की रफ्तार बहुत धीमी है। उदाहरण के लिए केवल 1.2 प्रतिशत भूमि ही माइक्रो इरिगेशन यानी लघु सिंचाई से कवर हो पाई है। यह कर्नाटक और तमिलनाडु के मुकाबले बहुत कम है। कर्नाटक में जहां बीस प्रतिशत भूमि माइक्रो इरिगेशन के दायरे में है, वहीं तमिलनाडु में यह 15 प्रतिशत है। इस लिहाज से पंजाब को यहां तक पहुंचने में वर्षों लगेंगे और अगर पानी की बात की जाए तो राज्य के पास इतना समय शायद अब नहीं रह गया है। सिंचाई ही नहीं, पंजाब की केवल 0.002 प्रतिशत जमीन पर ही जैविक खेती हो पा रही है। ग्रीनहाउस अथवा पालीहाउस आधारित खेती को अपनाने के मामले में पंजाब की रफ्तार देश में सबसे पीछे वाले राज्यों से मुकाबला कर रही है। इसी से जुड़ी एक सच्चाई यह है कि देश में कीटनाशकों की सबसे अधिक खपत यदि किसी राज्य में है तो वह पंजाब ही है। यहां 0.74 किग्रा/हेक्टेयर कीटनाशकों की खपत है।

Navbharat Times- 16- February-2024

यमुना को प्रदूषण से बचाने में दिल्ली फिर फेल! सिर्फ पल्ला में ही पानी थोड़ा साफ

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

AI Image

सीपीसीबी ने यमुना नदी की 12 लोकेशन पर वॉटर क्वॉलिटी की जांच की

सेंट्रल पल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मुताबिक, दिल्ली अब भी अपनी इकलौती नदी को यहां प्रदूषण से बचा पाने में नाकाम है। बोर्ड ने दिल्ली-एनसीआर में यमुना के पानी की क्वॉलिटी की जांच के संबंध में अपनी स्टेटस रिपोर्ट नैशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में दाखिल की है। इसके मुताबिक, दिल्ली में यमुना के सात लोकेशन पर पानी की जांच में केवल पल्ला ही पास हुआ, बाकी छह लोकेशन इस पैमाने पर फेल हो गईं।

CPCB ने यमुना के पानी की जांच पर रिपोर्ट दी

रिपोर्ट के मुताबिक, सीपीसीबी ने इस नदी की 12 लोकेशन पर वॉटर क्वालिटी की जांच की, जिनमें से छह हरियाणा और छह दिल्ली की हैं। हरियाणा में नदी की छह में से दो लोकेशन पर बीओडी तय मानकों के अनुरूप नहीं मिला। इनमें से एक मंगलौरा, करनाल और दूसरी जगह खोजकीपुर, पानीपत है। बाकी सभी लोकेशन जांच में पास हो गईं। दूसरी तरफ, दिल्ली में पल्ला को छोड़कर बाकी किसी भी लोकेशन पर डिसॉल्व्ड ऑक्सिजन, बीओडी और फीकल कोलिफॉर्म तय मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। रिपोर्ट के हवाले से, दिल्ली में कुल 24 नाले यमुना में गिर रहे हैं। इनमें से अधिकांश नालों का दूषित पानी नदी को प्रदूषित करता हुआ मिला। इनमें सोनिया विहार ड्रेन, नजफगढ़ ड्रेन, सप्लिमेंट्री ड्रेन, आईएसबीटी ड्रेन, शास्त्री पार्क ड्रेन , कैलाश नगर ड्रेन, दिल्ली गेट ड्रेन, सेन नूरसिंह होम, बारापूला ड्रेन, महारानी बाग ड्रेन, अब्दुल फजल ड्रेन, जैतपुर ड्रेन, मोलड़बंद ड्रेन, तुगलकाबाद ड्रेन, शाहदरा ड्रेन शामिल हैं।

एसटीपी के बारे में कहा गया कि यहां 19 में से केवल एक एसटीपी- केशोपुर फेज 3 ही तय मानकों के अनुरूप संचालित होता हुआ पाया गया।

Rajasthan Patrika- 16- February-2024

नर्मदा जयंती विशेष: एक जीवित आध्यात्मिक चेतना है मां नर्मदा

कुछ नदियों में पानी बहता है, लेकिन कुछ नदियों में मनुष्यता का इतिहास बहता है। कुछ नदियों के किनारे की चट्टानों में जीवन के निशान होते हैं और इन नदियों के आसपास की चट्टानों में सभ्यता के प्रमाण हैं, कुछ नदियों का सौन्दर्य मन मोह लेता है, लेकिन नर्मदा नदी मन हर लेती है। नर्मदा नदी में आत्मा भीग जाती है। दुनिया की एक मात्र नदी नर्मदा है, जिसकी परिक्रमा की जाती है। क्योंकि यह एक जीवित आध्यात्मिक चेतना है।

नमामि देवी नर्मदे...

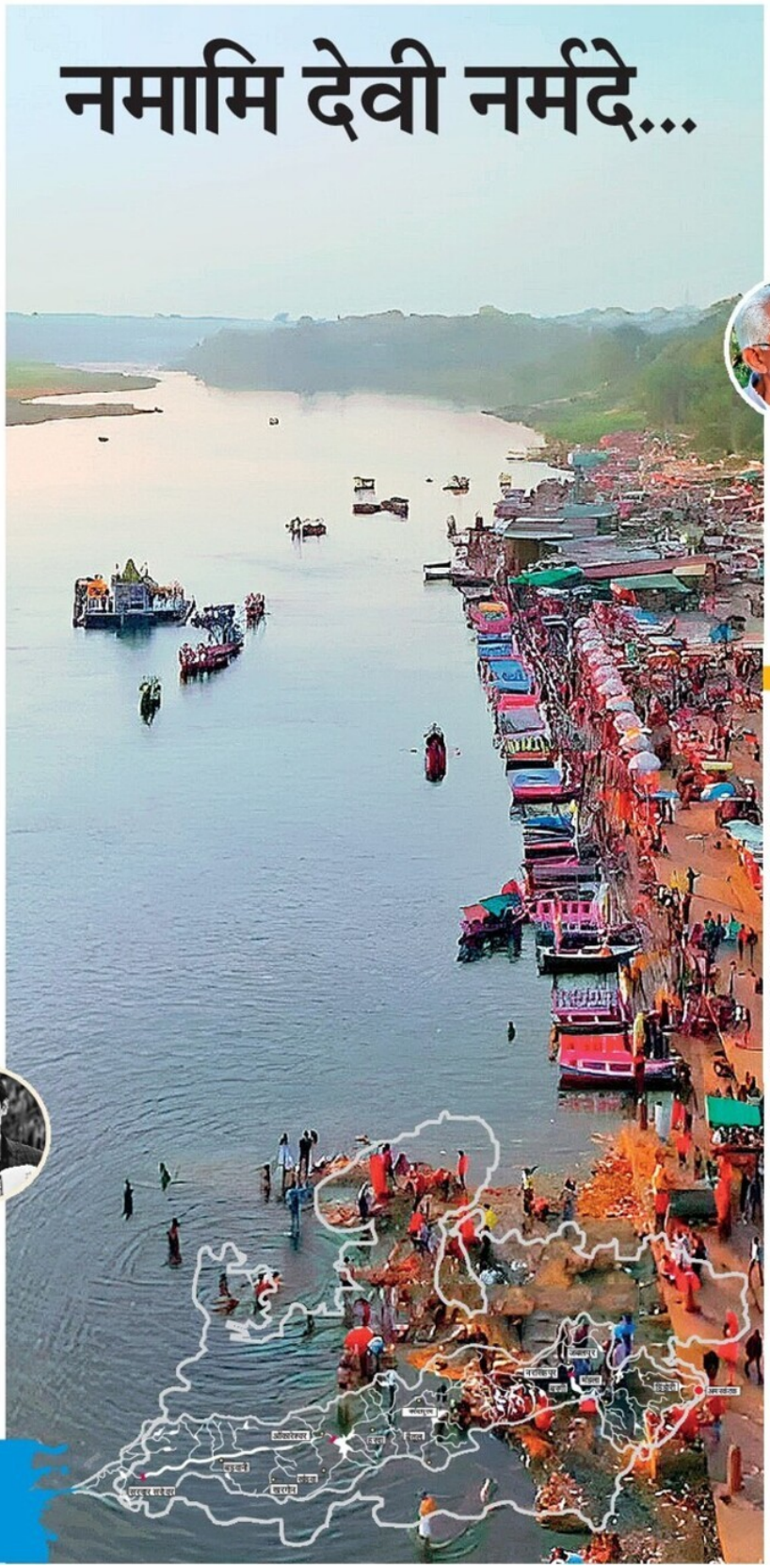

नर्मदा, समूचे विश्व मे दिव्य व रहस्यमयी नदी है, इसकी महिमा का वर्णन चारों वेदों की व्याख्या में वेदव्यास ने स्कन्द पुराण के रेवाखंड में किया है। इस नदी का प्राकट्य ही, विष्णु द्वारा अवतारों में किए राक्षस-वध के प्रायश्चित के लिए ही प्रभु शिव द्वारा अमरकंटक के मैकल पर्वत पर कृपा सागर भगवान शंकर द्वारा 12 वर्ष की दिव्य कन्या के रूप में किया गया। अमरकंटक को मां का शिरोभाग माना गया है तो भरुच(गुजरात) को पैर। नर्मदा का सनातन धर्म में विशेष स्थान है। पुराणों के अनुसार शिव से ही नर्मदा की उत्पत्ति हुई है। इसलिए उन्हें शिव की पुत्री माना है। नर्मदा का सामान्य जन-जीवन में महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे जन्म और विवाह से लेकर मृत्यु तक के संस्कारों में किसी न किसी रूप में नर्मदा शामिल होती है। नर्मदा को जीवित इकाई माना जाता है, वह आस्था में, संस्कृति-संस्कार और अध्यात्म में जीवित है।

नर्मदा के दो स्वरूप

नर्मदा पर माई टाइटिल से डॉक्यूमेंट्री बना रहे सुधीर आजाद कहते हैं कि अगर नर्मदा को समझना है तो दो हिस्सों में इसे जानना होगा। सदानीरा अरण्यों में बसनेवाली और देवताओं समेत तपस्वियों, ऋषियों, मुनियों की तपस्या भूमि मां नर्मदा है। जिसकी लहरों में मनुष्यता का कल्याण प्रवाहमान है। नर्मदा आस्थाओं का दिव्य समुच्चय है। एक जीवित आध्यात्मिक चेतना है मां नर्मदा। एक स्वरूप है धार्मिक, ऐतिहासिक, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक संदर्भ का। जिसे मां नर्मदा ने लाखों साल से मध्यप्रदेश से लेकर गुजरात तक के गांवों और शहरों में चेतना का संचार किया है।

35 किमी मप्र-महाराष्ट्र और

39 किमी मप्र-गुजरात सीमा

जैसा नर्मदा पुत्र अमृतलाल वेगड़ ने देखा

कितना रोमांचक होता है नदी के संग-संग चलना। हर स्थान नया, हर भोर नई। इन पदयात्राओं ने मेरे लिए पकृति सौंदर्य के न जाने कितने बंद दरवाजों को खुलवाए। सोई नदी को, जागते तारों को, मंडराते बादलों, निस्तब्ध वनों को, लहराते खेतों को, पशुओं के खुरों की छाप को, पत्तों पर पड़ती ओस के कणों की थाप को, मछुआरों की नावों को, नदी तट के गांवों को। इन सभी को देखकर मन विस्मय विमुग्ध होता रहता है। इससे अधिक आनंदमय और क्या हो सकता है? लेकिन संसार के यथार्थ की मार के कारण लोग कहां चल पाते हैं।

तीरे-तीरे नर्मदा यात्रा वृतांत

यह ठीक है कि नदी के दो किनारे होते हैं, पर हमारे काम का तो वही किनारा आता है, जो हमारी होता है। यहां हम नहा सकते हैं, बच्चे तैर सकते हैं, पनिहारिनें पानी भर सकती हैं, हमारी ओर का किनारा हमारे लिए अनेक प्रकार से कल्याणकारी है। सामने का तट का हमारे लिए वैसा कोई उपयोग नहीं। यहां बैठे-बैठे केलव उसके सौंदर्य को देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि नदी सत्य है, हमारी ओर का किनारा शिव है, सामने का किनारा सुंदर है। सत्यम्, शिवम्, सुंदरम।

मां से पहली भिक्षा लेकर नर्मदा परिक्रमा की: प्रहलाद पटेल

नर्मदा परिक्रमा करने वाले कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल ने संस्मरण सुनाते हुए बताया कि बाबाश्री के सान्निध्य में उन्हें यह अवसर मिला था। व्रत और समर्पण निष्ठापूर्वक की जाने वाली नर्मदा परिक्रमा 3 वर्ष 3 माह और 13 दिन में पूरी करने का विधान है। गुरु आदेश से उन्होंने परिवार को परिक्रमा की जानकारी दी और अनुमति ली। पहली भिक्षा मां से लेकर घर से निकले। जनश्रुति है कि अश्वत्थामा अभी नर्मदा की परिक्रमा कर रहे हैं।